Publication Name: The Tribune
Publication Date: 15/09/2025
Edition: Delhi
Page No: 5
CCM: 278.59

Agnihotri seeks funds for expansion of cooperatives

Urges Union Minister for aid for computerisation of societies, digitisation of Himfed, Milkfed

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, SEPTEMBER 14

Union Minister of State for Cooperation Krishan Pal Gurjar today said that the development and expansion of the cooperative sector was mandatory to make farmers prosperous and self-dependent. He called Himachal an ideal state for cooperatives while reviewing various centrally-sponsored initiatives aimed at strengthening the sector at a meeting of the Himachal Pradesh Cooperative Department here. He launched 121 e-PACS on the occasion.

Deputy CM Mukesh Agnihotri honours Union Minister of State for Cooperation Krishan Pal Gurjar in Shimla on Sunday.

The Union Minister said that various cooperative courses would be started in the state under Tribhuvan Sahkari University, the country's only national cooperative university. "The state has submitted a proposal in this regard. There are some issues regarding fees, which will be sorted out," he added.

Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri said that the draft of the Himachal Pradesh State Cooperative Policy-2025 had been prepared in line with the Central cooperative policies to expand cooperatives in the state. He requested Gurjar to extend generous support to the state in this field and sought funds for the computerisation of societies and support for the digitisation of Himfed and Milkfed. He urged the Union Minister for financial assistance for HIMCAPS College of Law in Una district. Gurjar assured Agnihotri that the Central Government would provide every possible assistance to the state in the field of cooperatives.

Agnihotri said that about 20 lakh people in the state were associated with cooperatives and the cooperative societies here were setting an example in women empowerment. At present, 2,287 primary Agricultural Credit Societies were working towards rural financial inclusion. In this direction, six new multi-purpose societies had been formed. As many as 76 societies were serving the fishermen community, 971 dairy societies were engaged in milk production and distribution, 441 societies were providing savings and credit facilities and 386 primary marketing cooperative societies were helping farmers sell their produce.

"Himachal is also progressing in the dairy sector and 561 new societies have been established," said the Deputy Chief Minister. During the meeting, the representatives of various cooperative societies highlighted their achievements.

Powered By: Sahana System Limited

Publication Name: Dainik Jagran
Publication Date: 15/09/2025
Edition: Shimla
Page No: 2
CCM: 605.55

Priority to Empower Farmers Through Cooperatives

Union Minister Gurjar said that Himachal is called 'Fruit Bowl of the Country' only because of hardworking farmers.

सहकारिता से किसानों को सशक्त बनाना प्राथमिकता

केंद्रीय मंत्री गुर्जर ने कहा, मेहनतकश किसानों की बदौलत ही हिमाचल 'देश का फल कटोरा' कहलाता

प्रकाश भारद्वाज • जागरण

- केंद्र और राज्य सरकारों का साझा लक्ष्य किसान की समृद्धि रुकावट नहीं आने दी जाएगी
- उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अधिकारियों के साथ सहकारी क्षेत्र की समीक्षा बैठक

शिमलाः केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को शिमला में कहा कि सहकारिता के माध्यम से बागबानों और किसानों को सशक्त बनाना केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता है। हिमाचल "देश का फल कटोरा" है और यहां के मेहनती लोगों की विशेष पहचान है। गुर्जर ने मरीना होटल में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और राज्य के अधिकारियों के साथ सहकारी क्षेत्र की समीक्षा बैठक की। बैठक में किसानों, बागबानों और सहकारी संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का "सहकार से समृद्धि" का सिद्धांत वर्ष 2047 तक विकसित भारत की नींव बनेगा। केंद्र और राज्य सरकारों का साझा लक्ष्य किसान की समृद्धि है और इस दिशा में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी।

गुर्जर ने केंद्र सरकार की तीन प्रमुख सहकारी संस्थाओं एनसीसीएफ, एनसीडीसी और बीबीएमएस की योजनाओं पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और हिमाचल के किसी संस्थान को इससे जोड़े जाने पर राज्य को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा। पहाड़ी राज्यों के लिए इसमें संबद्धता फीस में कमी लाने पर विचार होगा। सहकारी बैंकों की मजबूती के लिए मिलकर रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इसके लिए संस्थागत ढांचा खड़ा करना जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हिमाचल की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करेगी।प्रदेश फलों का कटोरा है, इसलिए यहां भंडारण की विशेष योजनाएं लागू करने परविचार करेगा। इस अवसर पर 121 ई-पैक्स का शुभारंभ भी किया गया।

शिमला में रविवार को समीक्षा बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को हिमाचली परंपरा का प्रतीक स्मृति चिह्न भेंट करते उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री • सौ. डीपीआरओ

'हिमकैप्स कालेज आफ ला' के लिए दें सहायता : मुकेश

शिमलाः उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री से प्रदेश को इस क्षेत्र में उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने और हिमफेड तथा मिल्कफेड के डिजिटाइजेशन के लिए सहयोग की मांग की। उन्होंने ऊना जिले के 'हिमकैप्स कालेज आफ ला' को शीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सहकारिता क्षेत्र में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। । मुकेश ने कहा कि कहा कि राज्य में सहकारिता को विस्तार देने के लिए केंद्र की सहकारी नीतियों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी नीति 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं, और प्रदेश की सहकारी समितियां महिला सशक्तीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। वर्तमान में 2,287 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण वित्तीय समावेशन का कार्य कर रही हैं। इस दिशा में छह नई बहुउद्देशीय समितियां गठित की गई हैं। प्रदेश में 76 समितियां मछली पालन, 971 डेरी समितियां दूध उत्पादन एवं वितरण, 441 समितियां बचत एवं ऋण सुविधा, और 386 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां किसानों को अपनी उपज बेचने में सहायता कर रही हैं।

सफलता की कहानी लाभार्थियों की जुवानी

हमें किसानों की केसीसी करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि विभाग उचित समझे, तो हमें पोर्टल संचालन की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि हम अपने सदस्यों को घर बैठे सुविधाएं दे सकें। दि कुठेड़ा कृषि सेवा सहकारी सभा ने वर्ष 2024-25 में 264 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। सभा की बैलेंस शीट 90 करोड़ रुपये की है और इसके 3150 सदस्य हैं। सभा को 2024 में राष्ट्रीय सहकारी निगम द्वारा राज्य की सर्वश्रेष्ठ सहकारी सभा के रूप में पुरस्कृत किया गया। सभा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र और लोकमित्र केंद्र का कार्य कर रही है। इसके अलावा, सभा अपने सदस्यों को सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। वर्ष 2024 में सभा ने 93 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में अपने समान की प्रदर्शनी भी लगाई है।

-**अशोक शर्मा**, सचिव दि कुठेड़ा कृषि सेवा सहकारी सभा हमीरपुर।

हमारी सहकारी समिति विश्व के दस देशों में कारपेट निर्यात करती है। 200 लोगों की समिति में 110 कारीगर हैं, जिनमें 85 महिलाएं शामिल हैं। हम लगातार मुनाफा कमाते आ रहे हैं, जो 30 लाख से लेकर 60 लाख तक वार्षिक होता है। वर्ष 1969 में तिब्बती हस्तशिल्प उत्पादन एवं बिक्री सहकारी औद्योगिक समिति धर्मशाला का पंजीकरण हुआ। यह समिति धर्मशाला में तिब्बतियों के लिए आर्थिक जीवन रेखा का कार्य करती है। पारंपरिक हस्तशिल्प की बिक्री के माध्यम से कारीगरों को पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। समिति का प्रत्येक कारीगर शेयर धारक है और 1989 में निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, यह आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान में कारपेट निर्यात करती है। ऋण सुविधा मिलने पर, हम 30 से 40 देशों को कारपेट निर्यात करने का लक्ष्य रखते हैं।

-**तेंजिंग रिगसांग**, महाप्रबंधक, तिब्बती हस्तशिल्प उत्पादन एवं बिक्री सहकारी औद्योगिक समिति धर्मशाला।

भुट्टिको बुनकर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सहकारी समिति, कुल्लू, 1944 में केवल 23 रुपये की पूंजी से स्थापित हुई थी। यह संस्था कुल्लू घाटी के भुट्टिको गांव में स्थित है और विश्व स्तर पर शाल, टोपी, मफलर, तथा पसमीना शाल के लिए प्रसिद्ध है। भुट्टिको महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उन्हें प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित कर रही है। यह संस्था आधुनिक विपणन रणनीतियों को अपनाते हुए आनलाइन शापिंग में भी सक्रिय है। भुट्टिको यूरोपीय संघ, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने उत्पादों का निर्यात करती है। पिछले वर्ष, भुट्टिको ने 13 .22 लाख का टर्नओवर और 10 .55 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

-**नीना ठाकुर**, प्रबंधक भुट्टिको बुनकर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सहकारी समिति कुल्लू।

सभा द्वारा सस्ते ऋण, खाद और बीज की उपलब्धता और सस्ती दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। 1998 में खरीदी भूमि पर भवनों और गोदामों का निर्माण किया गया। तीन मंजिला भवन में कार्यालय, उचित मूल्य की दुकान, और लोक मित्र केंद्र शामिल हैं। वर्ष 2022 में नाबार्ड द्वारा दिए ऋण से ग्राम कंड़ा के ठाकुरद्वारा में भवन का निर्माण हुआ। यहां जन औषधि केंद्र, किसान सेवा केंद्र, और उचित मूल्य की दुकान स्थापित की गई हैं। वर्ष 2022-23 में सभा का कुल लाभ 11 .38 लाख रुपये रहा, और वर्तमान में मासिक दो लाख रुपये किराए के रूप में प्राप्त हो रहे हैं।

-**कुलदीप शर्मा**, सचिव, कंड़ा कृषि सहकारी सभा समिति धर्मपुर सोलन।

हमारी सहकारी सभा की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी और तब से लेकर आज तक बैंकिंग, शापिंग माल, प्रिंटिंग प्रेस, जीवन ज्योति क्लीनिक, रोजमर्रा की वस्तुओं की दुकान, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, हार्डवेयर का कारोबार कर रही है। वर्ष 2023 में 80 लाख का ऋण लेकर सहकार भवन का निर्माण किया गया। अब सहकारी समिति पेट्रोल पंप, भंडारण के क्षेत्र में कार्य करना चाहती है। दूसरी सहकारी समितियों को स्वेच्छा से इसमें शामिल होने का अवसर दिया गया।

-**हेमंत कुमार**, सचिव चामियां कृषि सहकारी सभा कसौली।

SAHANA system limited
Powered By: Sahana System Limited

Publication Name: Dainik Jagran
Publication Date: 15/09/2025
Edition: Shimla
Page No: 2
CCM: 207.26

Cooperative Societies to be Considered for Concessions in Section 118: CM

सहकारी समितियों को धारा 118 में रियायत पर होगा विचार : सीएम

शिमला में रविवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व अन्य● सौ. डीपीआरओ

- राज्य सहकारी बैंक में होगी छोटे किसानों के लिए ओटीएस लागू
- साइबर सिक्योरिटी आपरेशन सेंटर का शुभारंभ भी किया

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला : शिमला में रविवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का समापन हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे जोत आकार के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सहकारी समितियों को कारोबार के लिए भूमि ख़रीदने पर धारा 118 की अनुमति में रियायतों पर सरकार विचार करेगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक छोटे किसानों, बागवानों, मजदूरों और व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पालिसी (ओटीएस) लागू करेगा।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में पिछली सरकार के कार्यकाल से चली आ रही धांधलियों के चलते वर्तमान राज्य सरकार ने पूरे बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में साइबर सिक्योरिटी आपरेशन सेंटर का शुभारंभ किया, बैंक का सहकार गान लांच किया और एक स्मारिका का विमोचन भी किया। इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को ध्यान में रखते हुए युवाओं को 'सहकार टैक्सी योजना' से जोड़ा जा सकता है। उत्तराखंड में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता आज देश में एक बड़ी पहचान बन चुकी है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन देवेंद्र श्याम, जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा, राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन संजय सिंह चौहान, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा के चेयरमैन के. रविंद्र राव, भारत सरकार में संयुक्त सचिव रमन कुमार सहित विभिन्न राज्यों की सहकारी सभाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

SAHANA system limited
Powered By: Sahana System Limited

Publication Name: Dainik Bhaskar
Publication Date: 15/09/2025
Edition: Shimla
Page No: 5
CCM: 228.79

20 Lakh People Join Cooperatives, Union Minister Says - We Are Ready to Help

सहकारिता विभाग की बैठक में कृष्ण पाल गुर्जर ने 121 ई-पैक्स का किया शुभारंभ

20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े, केंद्रीय राज्य मंत्री बोले- मदद के लिए हम तैयार

▪ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश कर रहा देश का पथ प्रदर्शन

भास्कर न्यूज|शिमला

केंद्र सरकार हिमाचल की सहकारिता के क्षेत्र में हर संभव मदद करेगी। ये बात सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने शिमला में कही। वे सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न पहलों पर शिमला में हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विविधता से पूर्ण हिमाचल में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर उन्होंने 121 ई-पैक्स (मेंबरशिप ड्राइव) का शुभारंभ भी किया। बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सहकारिता की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सहकारिता का जनक है और सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल ने देश को एक नई राह दिखाई है। प्रदेश में सहकारी समितियां बेहतरीन कार्य कर रही हैं। भरोसे का दूसरा नाम सहकारिता है, जिसके बल पर प्रदेश की सहकारी समितियों ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान स्थापित की है और सफलता की नई बुलंदियों को छुआ है। हिमाचल में लगभग 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और प्रदेश की सहकारी समितियां महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही है। वर्तमान में 2287 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण वित्तीय समावेशन का कार्य कर रही हैं।

शिमला में 121 ई-पैक्स का शुभारंभ करते सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर।

सहकारिता क्षेत्र में 561 नई समितियां गठित

प्रदेश में 76 समितियां मछली पालन समुदाय, 971 डेयरी समितियां दूध उत्पादन एवं वितरण, 441 समितियां बचत एवं ऋण सुविधा और 386 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही है। हिमाचल डेयरी क्षेत्र में भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इस क्षेत्र में 561 नई समितियां गठित की गई है। बैठक में उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारिता को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र की सहकारी नीतियों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी नीति 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। डिप्टी सीएम ने ऊना जिला के 'हिमकैप्स कॉलेज ऑफ लॉ' को शीघ्र वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव रमन कुमार, हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव सहकारिता सी पॉलरासु, कोऑपरेटिव बैंकों के एमडी और विभिन्न सहकारिता समूहों के सदस्य उपस्थित रहे।

SAHANA system limited
Powered By: Sahana System Limited

Publication Name: Deccan Chronicle
Publication Date: 15/09/2025
Edition: Chennai
Page No: 7
CCM: 2523.22

Himachal ideal state for co-ops: Minister

Shimla: Union minister of state for cooperation Krishan Pal Gurjar on Sunday described Himachal Pradesh as an ideal state for cooperatives. Chairing a meeting of the Himachal Pradesh cooperative department on Sunday to review the various Centre-sponsored initiatives aimed at strengthening the cooperative sector, the Union minister said there are immense possibilities in this field in a diverse state like Himachal. On this occasion, Mr Gurjar launched 121 e-PACS, which refer to the electronic transformation of primary agricultural credit societies (Pacs), enabling them to deliver digital services and function as common service centres. The Union minister assured that the Centre would provide Himachal Pradesh every possible assistance in the field of cooperatives. — *PTI*

Powered By: Sahana System Limited

Publication Name: Divya Himachal
Publication Date: 15/09/2025
Edition: Shimla
Page No: 2
CCM: 352.03

Adopt Cooperative Societies for Eco-Tourism and Taxi Services: Central Cooperative Minister Krishnapal Gurjar Speaks at Review Meeting in Shimla

ईको टूरिज्म, टैक्सी सेवा अपनाएं सहकारी समितियां

शिमला में समीक्षा बैठक में बोले केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर

दिव्य हिमाचल ब्यूरो – शिमला

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहकारिता के लिए आदर्श राज्य है, लेकिन इस क्षेत्र में अब विविधता की अपार संभावनाएं हैं। वह रविवार को शिमला में सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न पहलों पर हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल में प्राथमिक क्षेत्र में सहकारी समितियों का अच्छा खासा नेटवर्क है। उन्हें अपने काम और बिजनेस में विविधता लाने की जरूरत है। डायवर्सिफिकेशन करना होगा। सरकारी समितियां टैक्सी सेवा, फूड प्रोसेसिंग के साथ-साथ होम स्टे और ईको टूरिज्म को भी अपने काम में शामिल करें। इससे न सिर्फ काम का दायरा बढ़ेगा, बल्कि लोगों को रोजगार और स्वरोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने 121 ई-पैक्स का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी थे।

उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए स्थापित की जा रही त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की फीस निर्धारण पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया। राज्य का सहकारिता विभाग ऊना में एक सेटेलाइट सस्थान खोलने जा रहा है।

केंद्र सरकार करेगी मदद

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सहकारिता क्षेत्र में केंद्र द्वारा हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस दौरान रजिस्ट्रार सहकारी समिति डीसी नेगी ने प्रेजेंटेशन दी। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव रमन कुमार, हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव सहकारिता सी. पालरासु, को-ऑपरेटिव बैंकों के एमडी, हिमफेड, मिल्कफेड, इफको के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न सहकारिता समूहों के सदस्य उपस्थित थे।

शिमला – यहां आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को सम्मानित करते उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

सहकारिता के विकास में मदद करे केंद्र

डिप्टी सीएम ने हिमफेड-मिल्कफेड की डिजिटाइजेशन के लिए भी मांगा सहयोग

दिव्य हिमाचल ब्यूरो – शिमला

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सहकारिता की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारिता को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र की सहकारी नीतियों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी नीति 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री से प्रदेश को इस क्षेत्र में उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सहकारिता का जनक है और सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल ने देश को एक नई राह दिखाई है। प्रदेश में सहकारी समितियां बेहतरीन कार्य कर रही हैं। हिमाचल में लगभग 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और प्रदेश की सहकारी समितियां महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही हैं। वर्तमान में 2,287 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण वित्तीय समावेशन का कार्य कर रही है। इस दिशा में छह नई बहुउद्देश्यीय समितियां गठित की गई हैं। प्रदेश में 76 समितियां मछली पालन समुदाय, 971 डेयरी समितियां दूध उत्पादन एवं वितरण, 441 समितियां बचत एवं ऋण सुविधा और 386 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही हैं। हिमाचल डेयरी क्षेत्र में भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इस क्षेत्र में 561 नई समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने हिमफेड और मिल्कफेड का डिजिटाइजेशन करने के लिए केंद्र से सहयोग प्रदान करने को कहा। उन्होंने ऊना जिला के 'हिमकैप्स कॉलेज ऑफ लॉ' को शीघ्र वित्तीय सहयोग देने का अनुरोध भी किया।

SAHANA system limited
Powered By: Sahana System Limited

Publication Name: Himachal Dastak
Publication Date: 15/09/2025
Edition: Dharamshala
Page No: 3
CCM: 260.2

Ideal State for Himachal Cooperatives: Union Minister of State for Cooperation, Krishna Pal Gurjar Launches 121 e-PAX

हिमाचल सहकारिता के लिए आदर्श राज्य

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किया 121 ई-पैक्स का शुभारंभ

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

● डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले- राज्य में सहकारिता की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा

केंद्र सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने हिमाचल प्रदेश को सहकारिता के लिए आदर्श राज्य बताया। उन्होंने कहा कि विविधता से पूर्ण हिमाचल में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने 121 ई-पैक्स का भी शुभारंभ किया। शिमला में रविवार को हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सहकारिता की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सहकारिता का जनक है और सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल ने देश को एक नई राह दिखाई है। प्रदेश में सहकारी समितियां बेहतरीन कार्य कर रही हैं। भरोसे का दूसरा नाम सहकारिता है, जिसके बल पर प्रदेश की सहकारी समितियों ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान स्थापित की है तथा सफलता की नई बुलंदियों को हुआ। हिमाचल में लगभग 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और प्रदेश की सहकारी समितियां महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही हैं। वर्तमान में 2287 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण वित्तीय समावेशन का कार्य कर रही हैं। इस दिशा में 6 नई बहु-उद्देश्यीय समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री से प्रदेश को इस क्षेत्र में उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने तथा हिमफैड और मिल्कफैड का डिजिटाइजेशन करने के लिए सहयोग प्रदान करने को कहा। उन्होंने ऊना जिला के हिमकैप्स कॉलेज ऑफ लॉ को शीघ्र वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। प्रदेश में 76 समितियां मछली पालन समुदाय, 971 डेयरी समितियां दूध उत्पादन एवं वितरण, 441 समितियां बचत एवं ऋण सुविधा और 386 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही हैं। हिमाचल डेयरी क्षेत्र में भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इस क्षेत्र में 561 नई समितियां गठित की गई हैं। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारिता को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र की सहकारी नीतियों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी नीति 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। सहकारिता क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए स्थापित की जा रही त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की फीस निर्धारण पर पुनः विचार करने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सहकारिता क्षेत्र में केंद्र द्वारा हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने पूर्ण साक्षर राज्य की उपलब्धि हासिल करने पर प्रदेश सरकार को बधाई भी दी।

Powered By: Sahana System Limited

Publication Name: Veer Arjun
Publication Date: 15/09/2025
Edition: Delhi
Page No: 16
CCM: 137.9

Himachal is showing the way to the country in the field of cooperation: Deputy Chief Minister

हिमाचल, सहकारिता के क्षेत्र में देश का कर रहा पथ प्रदर्शन : उप-मुख्यमंत्री

शिमला, (पवन आश्री)। सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न पहलों पर आज शिमला में हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने हिमाचल प्रदेश को सहकारिता के लिए आदर्श राज्य बताया। उन्होंने कहा कि विविधता से पूर्ण हिमाचल में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर उन्होंने 121 ई-पैक्स का शुभारंभ भी किया।

बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सहकारिता की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सहकारिता का जनक है और सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल ने देश को एक नई राह दिखाई है। प्रदेश में सहकारी

समितियां बेहतरीन कार्य कर रही हैं। भरोसे का दूसरा नाम सहकारिता है जिसके बल पर प्रदेश की सहकारी समितियों ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान स्थापित की है तथा सफलता की नई बुलंदियों को हुआ। हिमाचल में लगभग 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और प्रदेश की सहकारी समितियां महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही है। वर्तमान में 2,287 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण वित्तीय समावेशन का कार्य कर रही है। इस दिशा में 6 नई बहुउद्देशीय समितियां गठित की गई हैं। प्रदेश में 76 समितियां मछली पालन समुदाय, 971 डेयरी समितियां दूध उत्पादन एवं वितरण, 441 समितियां बचत एवं ऋण सुविधा और 386 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही है। हिमाचल डेयरी क्षेत्र में भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इस क्षेत्र में 561 नई समितियां गठित की गई है।

Powered By: Sahana System Limited